भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 65*
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

“आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेज”

*65. श्री जगदम्बिका पाल:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में शामिल किए जाने वाले पैकेजों की संख्या सहित आयुर्वेदिक पैकेजों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारों की व्यापक श्रृंखला प्रदान किए जाने के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) लाभार्थियों के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकल्प के रूप में आयुर्वेदिक उपचार को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) :

विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**लोक सभा में 29 नवंबर, 2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न
संख्या 65* के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का उद्देश्य भारत की जनसंख्या के निचले 40% हिस्से से संबंधित 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में 27 विशेषज्ञताओं के अंतर्गत 1,961 पैकेज शामिल किए गए हैं, जो पीएम-जेएवाई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी पूर्ववर्ती स्थितियों को पहले दिन से ही कवर किया जाता है और इन सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली निर्धारित प्रक्रियाओं की सूची शामिल होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में नए पैकेजों को, विभिन्न विशेषज्ञताओं के लिए स्थापित चिकित्सा विशेषज्ञ समितियों द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें प्रमुख संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

यह समिति नए पैकेज को शामिल करने की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है, जिसमें नैदानिक प्रासंगिकता, लागत-प्रभावशीलता, और प्रस्तावित पैकेजों के रोगी देखभाल और स्वास्थ्य परिणामों पर समग्र प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह समिति उपचार के मानक दिशानिर्देशों और आवश्यक दस्तावेजों को भी अंतिम रूप देती है, जो स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं को मार्गदर्शन देने और दावा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इस समिति की सिफारिशों की समीक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के स्वास्थ्य नीति और गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग द्वारा की जाती है और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, पैकेजों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज में शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ अंतिम रूप दिया जाता है।

आयुष पैकेजों को अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में शामिल नहीं किया गया है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : आयुष मंत्रालय ने लोगों के बीच आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

1) आयुष मंत्रालय देश में आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:-

- i. आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।
- ii. पीएचसी, सीएचसी और डीएच में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
- iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
- iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालयों (जो किराए पर हैं/जीर्ण-शीर्ण आवास में हैं) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।
- v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
- vi. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालोंको आवश्यक औषधियों की आपूर्ति।
- vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)।
- ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता समर्थन।

- x. आयुष ग्राम।
- xi. उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना करना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- xii. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास।
- xiii. आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मसी/ पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

2) आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 12 राष्ट्रीय संस्थान और 05 अनुसंधान परिषदें हैं जो आउट पेशेंट और इनडोर रोगी सेवाओं, आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन में लगी हुई हैं। ये संस्थान/परिषदें आम जनता के बीच स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आरोग्य मेलों, जागरूकता शिविरों, उपचार शिविरों, रेडियो और टीवी वार्ताओं, स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (एसआरपी), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम, जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी), मधुमेह कैंसर और स्ट्रोक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) जैसे आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। परिषदें, ठोस साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करती हैं जिनमें नैदानिक अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान, औषधि मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, फॉर्मिकोलोजिकल अनुसंधान और साहित्यिक एवं मौलिक अनुसंधान शामिल हैं।

3) "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के आयोजन के तहत, आयुष मंत्रालय के तहत सभी राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान परिषदों ने

वेबिनार, चिकित्सा शिविरों, औषधीय पौधों के रोपण, सार्वजनिक व्याख्यानोँ और आयुष दवाओं के वितरण का आयोजन किया है।

4) मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईसी स्कीम) विकसित की है जिसके तहत आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धन, विकास और मान्यता दिलाने में मदद देता है; हितधारकों के बीच बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष बाजार के विकास को बढ़ावा देता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना करके अकादमी और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरुकता एवं रुचि को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कायर्शालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

5) आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलें और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जैसे, आम जनता तथा आयुष चिकित्सकों के लिए एडवाजरी/दिशानिर्देश जारी किए हैं, अभियान चलाए हैं, आयुष जनशक्ति प्रशिक्षण दिया है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पत्र-व्यवहार किया है, अंतर-विषयक आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्यबल की स्थापना की है, 150 अंतर-विषयक अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से कोविड-19 पर अनुसंधान करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है, मानव संसाधन बढ़ाए हैं।

6) आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के संवर्धन, प्रचार और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए 2016 से हर साल धन्वंतरि त्रयोदशी के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में अधिसूचित किया है।

7) दिनांक 14 मार्च, 2024 तक, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम), आयुष मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, द्वारा देश भर में 541 आयुर्वेद कॉलेज अनुमोदित/पंजीकृत किए गए

हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 तक, देश में कुल 3885 आयुष अस्पताल हैं, जिनकी बिस्तर संबंधी क्षमता 62670 है। इनमें से 3005 अस्पताल आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से संबंधित हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 तक, देश में कुल 37,804 आयुष औषधालय हैं, जिनमें से 25,426 औषधालय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से संबंधित हैं। ये अस्पताल सामान्य जनता को रियायती दरों पर या निःशुल्क आयुर्वेदिक उपचार प्रदान कर रहे हैं।